हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
बुधवार, 21 सितंबर 2011, नगर/नोएडा, पांच प्रदेश, 16 संस्करण
www.livehindustan.com

हम क्यों पिछड़ रहे हैं उच्च शिक्षा में

विश्वस्तरीय संस्थान खड़े करने के लिए हमें ऐसी नीति चाहिए, जो स्वायत्तता, पारदर्शिता, विविधता और विश्वदृष्टि जैसे मूल्यों पर आधारित हो।

हरिवंश चतुर्वेदी
निदेशक, विमटेक

एक बार फिर दुनिया के शीर्षस्थ 200 विश्वविद्यालयों की सूची में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान का नाम नहीं है। क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2011 में पहले पांच स्थानों पर फिर वही कैंब्रिज यूनिवर्सिटी, हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी, एमआईटी, येल यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। पिछले साल इसी रैंकिंग में आईआईटी, मुंबई को 187वां स्थान मिला था, जो इस बार 225वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी तरह आईआईटी, दिल्ली 202वें स्थान से 218वें स्थान और आईआईटी, मद्रास 262वें स्थान से फिसलकर 281वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा की तीन लोकप्रिय रैंकिंग में से एक है क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसका निर्धारण शोध की गुणवत्ता, शैक्षणिक प्रतिष्ठा और नियोक्ताओं की साख के आधार पर किया जाता है। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग के बारे में अक्सर विवाद रहता है, क्योंकि अलग-अलग रैंकिंग के नतीजे कभी भी एक जैसे नहीं होते। इसका मुख्य कारण रैंकिंग की प्रणाली और प्रयुक्त पैमानों का कोई एक मॉडल न होना है।

क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जहां आईआईटी, मुंबई और आईआईटी, दिल्ली की रैंकिंग में गिरावट आई है, वहीं देश की अन्य जानी-मानी उच्च शिक्षा संस्थाओं, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय को सूची में कोई स्थान नहीं मिला है।

कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के नाम न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे संस्थान भारतीय विद्यार्थियों और नियोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह तर्क वैश्वीकरण के इस दौर में ठीक नहीं होगा, खासतौर से तब, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जा रही है। गौर से देखा जाए, तो दुनिया के ताकतवर व समृद्ध देशों की सफलता का एक बड़ा कारण विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा ही है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर, मलयेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की आर्थिक प्रगति को उनकी विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा से जोड़कर ही समझा जा सकता है। 21वीं सदी में औद्योगिक विकास का सीधा संबंध वित्तीय पूंजी, आधुनिक प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और प्रतिभाशाली जनशक्ति से है। वैश्वीकरण ने इन सभी मुख्य कारकों के बाजार को राष्ट्रीय सीमाओं से मुक्त कर दिया है। जिन देशों में इन कारकों को आकर्षित करने का दमखम है, वहां ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जो देश इन पर ध्यान नहीं देते, वहां से पूंजी, प्रतिभा, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और उद्यमी पलायन करने लगते हैं।

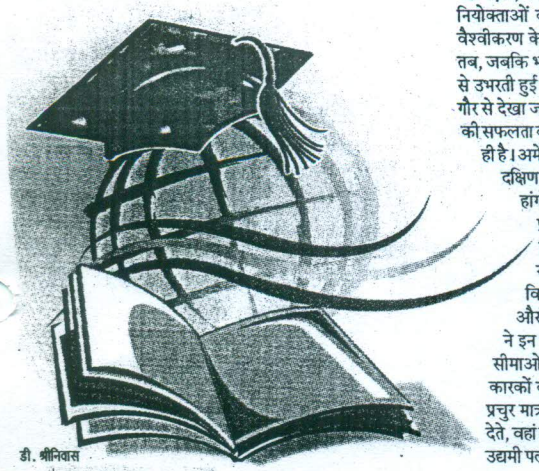

डी. श्रीनिवास

विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा और संस्थानों की सर्वप्रमुख विशिष्टता है कि वे शोध और अनुसंधान पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि कक्षा-शिक्षण पर। विश्वविख्यात शिक्षाशास्त्री प्रोफेसर फिलिप अल्टबाक का कथन है कि हर देश को ज्ञान की अर्थव्यवस्था में भागीदारी के लिए शोधपरक विश्वविद्यालयों की जरूरत होती है। ये विश्वविद्यालय, परंपरागत हमबोल्ट मॉडल के अनुरूप नए ज्ञान की खोज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चूंकि स्नातकोत्तर शिक्षण और पीएचडी कार्यक्रमों पर स्नातक कार्यक्रमों की तुलना में बहुत ज्यादा खर्च होता है, इन विश्वविद्यालयों को सिर्फ केंद्र सरकार के बलबूते पर चलाया जा सकता है। निजी क्षेत्र और राज्य सरकारें इन विश्वविद्यालयों में दिलचस्पी नहीं लेती हैं।

क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों की स्थिति भले ही दयनीय हो, किंतु इसी रैंकिंग में एशिया के शीर्षस्थ 200 विश्वविद्यालयों में कुछ भारतीय संस्थानों को सम्मानजनक रैंक दिया गया है। एशिया की सूची में आईआईटी कानपुर को 36वीं, आईआईटी मुंबई को 38वीं और आईआईटी दिल्ली को 37वीं रैंक दी गई है। देश के तीन शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों यानी दिल्ली विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय को भी इस सूची में स्थान मिला है। एशिया के 200 शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों की सूची में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और ताईवान का प्रभुत्व दिखाई देता है, जिनके क्रमशः 57, 40, 35 विश्वविद्यालयों व संस्थानों को इस सूची में स्थान मिला है। भारत को एशिया की सूची में पांचवा स्थान मिला है, इस सूची में मलयेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और हांगकांग के विश्वविद्यालयों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। चीन और दक्षिण कोरिया को एशिया की सूची में 50 प्रतिशत स्थान मिलना भारत के लिए एक सबक है, क्योंकि 60 वर्ष पूर्व तीनों देश उच्च शिक्षा में लगभग एक ही स्तर पर आंके जाते थे।

आज विश्व में जो उच्च शिक्षण संस्थान शिखर पर आसीन हैं, उनके इतिहास से हम कुछ सीख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड, हॉर्वर्ड, कैंब्रिज, एमआईटी, येल, स्टैनफर्ड जैसे विश्वविद्यालयों की सैंकड़ों वर्ष की समृद्धशाली परंपरा रही है, जिसमें अल्युमनाई, फैकल्टी, उद्योग जगत और सरकारों का भरपूर योगदान रहा है। इन संस्थानों के प्रबंधन में आमतौर पर एक विश्वदृष्टि का उपयोग किया गया है। पूरी दुनिया के प्रतिभाशाली नौजवान इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जी-जान से स्पर्द्धा करते हैं और ज्यादातर कर्ज लेकर पढ़ाई करते हैं।

क्या अगले 20 वर्ष में हम अपने 50 शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों और संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने का भागीरथ प्रयत्न कर सकते हैं? 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 30 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, आठ नए आईआईटी, सात नए आईआईएम, 37 अन्य तकनीकी संस्थान और जिला स्तर पर 373 नए कॉलेज स्थापित करने के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपये का आंबटन किया था। इनमें से ज्यादातर संस्थानों को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। उन संस्थानों से अभी विश्वस्तरीय गुणवत्ता तो दूर की बात है, राष्ट्रीय प्रतिमानों के अनुरूप कार्य करने की उम्मीद करना भी व्यर्थ है।

मौजूदा नीतियों के आधार पर विश्वस्तरीय संस्थान खड़े करना असंभव होगा। इन संस्थानों को चलाने के लिए ऐसी नीतियों की जरूरत होती है, जो उच्चस्तरीय अनुसंधान में लगे हुए फैकल्टी व विद्यार्थियों को जवाबदेही के साथ-साथ भरपूर स्वायत्तता और बौद्धिक स्वतंत्रता दे सके। उच्च शिक्षा में सरकार और निजी क्षेत्र की भूमिका तथा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश की अनुमति देने के मुद्दों पर अभी तक कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं बन पाई है। वर्ष 2031 तक 50 विश्वस्तरीय संस्थान खड़े करने के लिए हमें एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो स्वायत्तता, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, जवाबदेही, विविधता और विश्व दृष्टि जैसे मूल्यों पर आधारित हो। हमें एक ऐसे ढांचे की जरूरत है, जो दुनिया के शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों व संस्थानों में काम कर रहे भारतीय प्रोफेसरों व अनुसंधानकर्ताओं को भारत लौटने के लिए आकर्षित कर सके। वर्ष 2031 तक नालंदा और तक्षशिला जैसे पचास विश्वविद्यालयों को खड़ा करना एक दिवास्वप्न जरूर है, किंतु भारत जैसे महादेश के लिए यह असंभव नहीं होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)